क्षेत्रीय समाचार एकांश

देहरादून (उत्तराखण्ड)

शुक्रवार 20.06.2025

समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्‌घाटन और शिलान्यास करेंगी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 51 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
- प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए 30 जून को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।

<u>इंट्रो</u>

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्‌घाटन और शिलान्यास करेंगी। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मु राष्ट्रपति पार्क की आधारशिला भी रखेंगी। शेष ब्यौरा हमारी देहरादून संवाददाता से–

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्‌घाटन करेंगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन आम जनता के लिए 24 जून से खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त, श्रीमती मुर्मू 132 एकड़ में विकसित होने वाले राष्ट्रपति पार्क की आधारशिला भी रखेंगी। यह उद्यान एक वर्ष में पूर्ण होकर जनता को समर्पित किया जाएगा।

21 एकड़ में फैला राष्ट्रपति निकेतन पहले राष्ट्रपति आशियाना के नाम से जाना जाता था। यह परिसर पूर्व में राष्ट्रपति अंगरक्षकों द्वारा पीबीजी घोड़ों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता था। आम जनता के लिए खुले जाने के बाद, दर्शक राष्ट्रपति अंगरक्षकों के अस्तबल, घोड़ों और इस विरासत भवन में संरक्षित दुर्लभ कलाकृतियों का अवलोकन कर सकेंगे। इसके साथ ही, लिली पॉन्ड, रॉकरी पॉन्ड, रोज गार्डन जैसी सुंदर संरचनाएं भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी।

यह पहल राष्ट्रपति भवन की विरासत और राष्ट्रपति के साथ जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जा रही है। वहीं, 19 एकड़ में फैला राष्ट्रपति तपोवन आमजन को प्राकृतिक छाया, घुमावदार पगडंडियां, लकड़ी के पुल और ध्यान–चिंतन के लिए निर्मित शांत स्थलों का अनुभव प्रदान करेगा।

स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 51 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

इसमें देहरादून जिले में सीवरेज कार्यों की सात योजनाओं के लिए लगभग 31 करोड़, उधमसिंह नगर जिले के दिनेशपुर की दो योजनाओं के लिए सतानब्बे लाख और चमोली जिले के गोपेश्वर में भू–धंसाव रोकथाम योजना के लिए सात करोड़ 78 लाख रुपए शामिल हैं।

इसके अलावा बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में बदलने और चमोली जिले के थराली स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर कुलसारी में उप जिला चिकित्सालय स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।

बिजली उत्पादन

पिछले पांच वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बडा देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्यिक और आवासीय स्थानों का विस्तार, एयर कंडीशनर और अन्य घरेलू बिजली उपकरणों के बढते इस्तेमाल तथा उद्योगों की बढ़ती मांग ने इसमें योगदान दिया है।

निलंबन

पौड़ी जिले के रिखणीखाल ब्लॉक के वड्डाखाल क्षेत्र में बिजली लाइन पर काम करते समय संविदा लाइनमैन की करंट लगने से हुई मृत्यु की घटना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है।

लैंसडौन विधायक महंत दलीप सिंह रावत की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों के तहत संबंधित उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता और अधिशासी अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसके पास कितने सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं और क्या ये उपकरण फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों तक प्रभावी रूप से पहुंच रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार हर कर्मचारी की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निर्णय

देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय चंद्रबदनी (नैखरी) को पहली जुलाई से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के परिसर के रूप में स्थापित किया जाएगा। इससे छात्र–छात्राओं को कई लाभ मिलेंगे।

श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने बताया कि उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय परिसर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला 17 जून को हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया।

निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का उपयोग बढ़ावा दें।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य, जिला और विकास खंड स्तर पर आयोजित सभी सरकारी और अर्ध–सरकारी कार्यक्रमों में कैटरिंग की जरूरतों के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा, अतिथियों के स्वागत कार्यक्रमों में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद या 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड के उपहार भी उपयोग किए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में जलपान के लिए मिलेट और स्थानीय पोषक उत्पादों को प्रमुखता दी जाए और सरकारी परिसरों में कैंटीन अथवा आउटलेट संचालन के लिये स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए वित्त विभाग की नियमावली के अनुसार खरीदारी की जाए।

मॉक ड्रिल

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए 30 जून को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में इसकी तैयारी को लेकर ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।

श्री सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में मैदानी जिलों में बाढ़ नियंत्रण और विभागीय समन्वय को बेहतर बनाने के लिए मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए थे।

यह मॉक ड्रिल ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और चंपावत के उन क्षेत्रों में होगी, जहां पिछले वर्षों में लगातार जलभराव और बाढ़ की स्थिति बनी है।

वाइब्रेंट विपेज

उत्तरकाशी जिले में बाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सीमांत गांवों के समग्र विकास को लेकर जिला प्रशासन एवं भारतीय सेना के सहयोग से अंडर ऑफ सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में आधारभूत संरचना, स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादों के संवर्धन और पारंपरिक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना था। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल टिज्यू थॉमस ने बताया कि झाला गांव में एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। इस परियोजना से क्षेत्रीय किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि सीमांत गांवों में केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्वीकृति के तहत सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की योजना प्रगति पर है।

वन दरोगा परीक्षा

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 22 जून को आयोजित वन दरोगा परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है।

उधर, चमोली जिले में परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। परगना मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडेय ने बताया कि केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।

इसके अलावा, केंद्रों के पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र के भीतर किसी भी प्रकार का साहित्य, प्रेस नोट, पंपलेट, पोस्टर या बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी।

केन्द्रीय शिक्षा

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं को अहम भूमिका निभानी होगी। श्री प्रधान आज अजमेर के निकट राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नौवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दो दशकों में भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना देश के नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

- एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...
- इजराइल और ईरान युद्ध की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इसी खबर पर अपने शीर्षक में लिखा है– इजराइल ने परमाणु ठिकानों को बनाया निशाना, ईरान ने अस्पताल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें।
- दैनिक जागरण की ख़बर है– इजराइल के अस्पताल पर हमला, 200 घायल, नेतनयाहु ने खामनेई के खात्मे का संकल्प जताया।

- सरकारी आवास में नकदी मिलने के आरोपों का सामना कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की खबर को भी लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है– जांच समिति ने की जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश।
- दैनिक जागरण जांच समिति के हवाले से लिखता है– पद पर रहने लायक नहीं जस्टिस यशवंत वर्मा, हटाने की जरूरत। हिंदुस्तान समाचार पत्र इसी खबर पर लिखता है– जांच समिति ने रिपोर्ट में कहा, पद से हटाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य, जस्टिस वर्मा के थे जब्त नोट।
- उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले की खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा है–शासन ने देर रात फेंटे पत्ते, चार डीएम बदले।
- हिदुस्तान की ख़बर है– 32 आईएएस और 24 पीसीएस के दायित्व बदले।
- राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है– पौड़ी, रूद्रप्रयाग, चंपावत और उत्तरकाशी के डीएम बदले। वहीं, अमर उजाला लिखता है –चार जिलों के डीएम बदले, स्वाती भदौरिया पौड़ी, प्रशांत कुमार आर्य उत्तरकाशी और प्रतीक जैन रूद्रप्रयाग के डीएम बने।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर–

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 51 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
- प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए 30 जून को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।